उत्तर प्रदेश मे विकास केन्द्रों का पुनः निर्धारण

6428. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री आस मोहम्मद:

क्या प्रधान मंत्री 5 मई, 1994 को राज्य सभा मे अतारांकित प्रश्न संख्या 5925 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तावित विकास केन्द्रों के पुनःनिर्धारण के संबंध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) से (ग) पौड़ी गढ़वाल जैसे मूल स्थापना-स्थल को बरकरार रखने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया है और उक्त निर्णय के बारे में राज्य सरकार को बता दिया गया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

6429. **चौधरी हरमोहन सिंह:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 1994 के अन्त तक सार्वजनिक उपक्रमों की संख्या कितनी थी;

(ख) इन उद्यमों में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है;

(ग) क्या इस पूंजी में विदेशों से ऋण के रूप मे ली गई पूंजी भी सम्मिलित है;

(घ) यदि हां, तो विदेशी ऋण से प्राप्त पूंजी कितनी है;

(ङ) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान इन उपक्रमों को कितना वार्षिक वित्तीय घाटा हुआ और इनमें से प्रत्येक वर्ष के अन्त में इन उद्योगों में कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(च) सरकार ने इन उद्योगों द्वारा उठाए जा रहे घाटे को रोकने के लिए क्या कदम उठाए है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही): (क) और (ग) 31.3.1994 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 246 उद्यम थे और उनमें कुल 16332 करोड़ रुपए का पूंजीनिवेश किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) विदेशी ऋण का उद्यम-वार ब्यौरा 22.3.1995 को संसद में प्रस्तुत लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1993-94 के खण्ड-1 के विवरण संख्या 18 के अन्तर्गत वि०पृ० 106 से 113 तक पर उपलब्ध है।

(ङ) विगत तीन वर्ष के दौरान हानि का उद्यम वार ब्यौरा उपर्युक्त लोक उद्यम सर्वेक्षण के खण्ड-1 के विवरण सं० 7(ख) के अन्तर्गत वि० पृ० 46 से 49 तक पर उपलब्ध है जबकि वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 में पूंजी निवेश का उद्यम-वार ब्यौरा सर्वेक्षण के खण्ड-1 के विवरण सं० 16 के अन्तर्गत दिया गया है।

(च) हानि के नियंत्रित करने/लाभकारिता में सुधार करने सम्बन्धी कार्य उद्यम विशेष की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग होते हैं। बहरहाल, इस संबंध में किए जाने वाले कुछ उपायों में प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा सरकारी उद्यमों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा हेतु आवधिक बैठकों का आयोजन, निदेशक मण्डलों को अधिक शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा उनका व्यावसायीकरण, रुग्ण सरकारी उद्यमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सुपुर्दगी, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के माध्यम से आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों की संख्या में कमी, प्रौद्योगिकी समुत्रयन, अनुसंधान एवं विकास आदि शामिल हैं।

Performance of HMT International

6430. SHRI S. MUTHU MANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the HMT International, a division of Hindustan Machine Tools Limited (HMTL) has not done well in terms of export of its products during the financial year 1994-95;

(b) what is the total amount earned by way of exports through HMT International during the financial year 1994-95;

(c) whether it is also a fact that the HMT Limited is planning to close down its offices at Australia and Iran,

considering the fact that the functioning of the offices at the above two places became uneconomical and non-productive;

(d) whether it is also a fact that the HMT Limited has also not made any headway in starting work on the Rupee 130 crore contract it had won from Tehran Metro, Iran, for setting up of a metro workshop; and

(e) if so, what are the reasons therefor and what action the HMT Limited is planning to take to start the work on the said project?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) During 1994-95, the total value of exports of HMT (International) (HMT (I) was approximately Rs. 40 crore as against Rs. 48 crore during 1993-94. The fall was due to global recssion, lack of finances in trditional markets of HMT(I) and political and economic changes in eastern Europe and erstwhile USSR.

(c) HMT (I) offices are opened and closed from time to time depending upon the business potential of the region, viability etc. during 1994-95 the Australia and Iran offices were closed.

(d) and (e) Against stiff global competition, HMT(I) was awarded a contract in Iran by the Tehran Urban and Suburban Railway Co. (TUSRC) for settingh up a maintenance workshop valued at Rs. 130 crore. As per the terms of the contract, HMT (I) had performed its obligations towards the execution of the contract. TUSRC were, however, unable to open the Letter of Credit for supply of the machines and equipment due to their financial difficulties.

NRI investment proposals In Gujarat

6431. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of Non-Resident Indians who have come forward to invest in Gujarat State during the next financial year;

(b) the amount proposed to be invested by the NRIs during the above period; and

(c) the facilities offered by the State Government to those NRIs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) to (c) Since the introducation of New Industrial Policy in July 1991, till 30-4-95, Government have approved 72 proposals involving NRI Investment of about Rs. 446.30 crores for setting up industries in Gujarat. Details regarding plans and proposed investment by NRIs for next financial year are not available with the Governemnt since approvals are dependent on applications being made.

The State Government formulate their own incentive schemes and facilities for attracting NRI Investment in their States.

Welfare measures by PSUs

6432. SHRI SANATAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the target amount under welfare measures in the budget of each Public Sector Undertaking for the upliftment of the weaker sections of the society living in and around the township of each undertaking for the year 1995-96; and

(b) the details of programmes undertaken, undertaking-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b) The Public Sector Undertakings have full autonomy to identify and implement social activities keeping in view their financial ability to sustain such activities, operating environment and provisions in their Memoranda of Association/ Statutes. They are not required to obtain the approval of the Govt, for undertaking such activities.

Foreign investment in Orissa

6433. SHRI SANATAN BISI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state the details of projected and actual inflow